(ग) यदि हां, तो इसके लिए कितनी धन-राशि आबंटित की गई है और इसके कब तक शुरू किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) (क) से (ग) उड़ीसा में निर्माण के लिए निम्नलिखित नई लाइनें अनुमोदित की गई हैं ।

1990-91 के दौरान आबंटित धनराशि

1. कोरापुट-रायगडा 70.00 करोड़ रुपए

2. तालचेर-सम्बलपुर 25.00 करोड़ रुपए

इस समय यह बताना कठिन है कि रूपसा-बांगरीपोसी लाइन के आमान परिवर्तन का कार्य कब शुरू होगा । चालू वर्ष में इस परिवर्तन के लिए कोई आबंटन नहीं किया गया है ।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश को आबंटित धनराशि

3661. **कुमारी सईदा खातून :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ख) गोंदिया से जबलपुर तक की छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने के लिए क्या प्रावधान किया गया है; क्या इस योजना अवधि के दौरान इस पर निर्माण कार्य किए जाने का विचार है; यदि हां, तो इस लाइन पर कब तक काम शुरू किए जाने की संभावना है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) मध्य प्रदेश में मीटर लाइन से बड़ी लाइन में कोई आमान परिवर्तन परियोजना प्रगति पर नहीं है ।

(ख) गोंदिया-जाब्लपुर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की परियोजना को अनुमोदित नहीं किया गया है । इस समय यह बताना कठिन है कि यह परियोजना कब शुरू की जाएगी ।

बंधुआ मजदूर

3662. **कुमारी सुशीला तिरिया**
कुमारी संईदा खातून

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राज्यों में अभी तक बंधुआ मजदूर प्रथा जारी है;

(ख) मध्य प्रदेश और उड़ीसा में ऐसे जिले कितने हैं जहां इस संबंध में सर्वेक्षण किया गया है और इन जिलों में ऐसे बंधुआ मजदूरों की संख्या कितनी है जिन्हें मुक्त कराया गया है; और

(ग) ऐसे बंधुआ मजदूरों की संख्या कितनी है जिन्हें अभी मुक्त कराया जाना शेष है और सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) 12 राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, और राजस्थान से बंधुआ श्रमिकों के होने की सूचना दी गई है । इनमें से गुजरात और केरल की राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि 31 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार पता लगाए गए सभी बंधुआ श्रमिकों को पुनर्वासित किया जा चुका है । बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम 1976 के अधीन बंधुआ श्रमिकों का पता लगाने, उन्हें मुक्त कराने और उनके पुनर्वास का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है । अधिनियम के उपबंधों के प्रवर्तन की श्रम मंत्रालय द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है और राज्य सरकारों को परामर्श दिया जाता है कि वे बंधुआ

श्रमिकों का पता लगाने, उन्हें मुक्त कराने और पुनर्वास के मामले में विभिन्न उपाय करें। मध्य प्रदेश और उड़ीसा के राज्यों में बंधुआ श्रमिकों की संख्या के बारे में सर्वेक्षण संबंधी सूचना संबंधित राज्य सरकारों से मांगी गई है तथा उसके प्राप्त होने पर उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

रेलवे में कुप्रबन्ध

3663. **कुमारी सईदा खातुन**
कुमारी सुशीला तिरिया

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग को इस बात की जानकारी है कि रेलवे में कुप्रबंध व्याप्त है; यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ख) पूरे देश में रेल गाड़ियों की समय-सारणी में परिवर्तन करने के क्या कारण है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) रेलें एक सुगठित प्रबंध यूनिट है जो संसाधनों की तंगी के बावजूद उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने में समर्थ है।

(ख) उपलब्ध संसाधनों के भीतर सेवाओं में सुधार करने के लिए समय सारणी में परिवर्तन किए जाते है।

Dereservation of Vacancy of Assistant Executive Engineer by I.A.R.I.

3664. SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a post of Assistant Executive Engineer reserved for Scheduled Castes candidates was advertised by I.A.R.I., New Delhi sometime in 1984-85 for direct recruitment;

(b) whether it is also a fact that no recruitment was made to that post and the post has recently been dereserved and transferred to general category and taken over to the Departmental promotion quota; and

(c) if so, what steps Government propose to take up to restore this post to the quota of S.C. vacancies ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI NITISH KUMAR) : (a) Yes, Sir.

(b) The post which was advertised had initially fallen vacant temporarily due to the fact that the incumbent had proceeded on deputation. The vacancy, although advertised, was not filled up as the officer came back from deputation. The vacancy arose again on 11-4-1990, on the appointment of the incumbent to a higher post in the Indian Council of Agricultural Research. During this period there has been an amendment in the recruitment rules, as a result of which the promotion quota was increased from 20% to 33.1/3% necessitating revision in the SC/ST roster. While earlier the vacancy was to be filled up by direct recruitment by an SC candidate now due to an amendment in the recruitment rules the post is required to be filled up by promotion without any reservation.

(c) Does not arise.

Allotment of land to NDMC for construction of an Auto Workshop in Delhi

3665. SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether New Delhi Municipal Committee has requested the Central Government to allot some land for construction of an Auto Workshop to enable NDMC to shift its existing Auto Workshop from in front of the historical Valmiki Temple at Mandir Marg, New Delhi;

(b) if so, when the request for allotment of land was received by the Central Government;

(c) whether land has been allotted to the NDMC in fulfilment of the direction issued by the Supreme Court in 1987 on